साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 29 मार्च 2021, वर्ष-6, अंक-52

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

मंडी में खुलेगी अटल किसान क्लीनिक

कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को चेताया-डीपीआर के अनुसार होना चाहिए काम

घटिया काम हुआ तो लटका दूंगा उल्टा ठेकेदार पर दर्ज कराऊंगा एफआईआर

विशेष संवाददाता, भोपाल

सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री बनते ही विकास के द्वार खोल दिए हैं। प्रतिदिन विकास के नए काम प्रारंभ किए जा रहे हैं। यह बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल के साकेत नगर में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नए किसान विश्राम-गृह-सह-प्रशिक्षण केंद्र के भूमि-पूजन समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर किसान विश्राम-गृह-सह-प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण घटिया हुआ तो अधिकारियों को उल्टा टांग दूंगा और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। किसी को छोड़ूंगा नहीं। किसानों के लिए यह विश्राम गृह एम्स के पास बनाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए भी किया जाएगा। साथ ही जो भी किसान एम्स में इलाज के लिए आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था भी इसी में की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को हम किसान सम्मान कार्ड दे रहे हैं। हम मंडी में अटल किसान क्लीनिक खोल रहे हैं।

भोपाल में कृषक विश्राम-गृह-सह-प्रशिक्षण केन्द्र का किया भूमि-पूजन।

न खाऊंगा, न खाने दूंगा

मंत्री ने कहा कि यह देखने में आया है कि प्राइवेट बिल्डिंग तो अच्छी बनती हैं और कम लागत में बन जाती हैं। जबकि सरकारी बिल्डिंग ज्यादा लागत के बावजूद और घटिया बनती हैं। हम साफ कहते हैं कि हम न खाएंगे और न ही किसी को खाने देंगे। यह मोदी जी का नारा है। मैंने कह दिया है जो डीपीआर है उसके अनुसार काम होना चाहिए।

कुछ खास

31,000 वर्ग फीट में बनेगा कृषक विश्राम-गृह	8.84 करोड़ रुपए होगी भवन निर्माण की लागत
03 मंजिला का भू-तल के अतिरिक्त रहेगा भवन	02 करोड़ का प्रावधान फर्नीचर के लिए किया
18 महीने में तैयार किया जाएगा यह भवन	50 कृषकों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी

गांव-शहर में खत्म हो रहा भेद

हमारी सरकार महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है। गांधी जी ने कहा था कि किसान इस देश की आत्मा और मूल रीढ़ हैं। किसान का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों एवं गांवों का इतना विकास हो रहा है कि धीरे-धीरे गांव और शहर का भेद खत्म हो रहा है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

गोद लिए गांव 'लावारिस'

- देशभर में अभी तक 77,457 परियोजनाओं में से सिर्फ 48,988 ही हो पाई हैं पूरी
- एमपी के 101 गांवों की 2,828 परियोजनाओं में से 1,894 पूरी
- कोरोना की मार केंद्र व राज्य की विकास योजनाओं पर भी पड़ा
- पीएम के प्रथम कार्यकाल की अति-महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना के नतीजे हताश करने वाले
- सांसदों की अरुचि के चलते योजना हासिए पर, गांवों के विकास की मोदी सरकार की अवधारणा पर तो लग गया ग्रहण
- सख्त शासक माने जाने वाले पीएम मोदी भाजपा के सांसदों पर योजना के तहत गांवों के विकास का दबाव नहीं बना पाए
- ज्यादातर सांसद ऐसे हैं जिन्होंने गांवों को चुन तो लिया है, लेकिन गांव की तरक्की के कामों में वे फिसड्डी साबित हुए
- जिन सांसदों ने दबाव में गांवों को चुन भी लिया, अभी उन के द्वारा चुने गए पहले चरण के गांवों में ही विकास नहीं दिखा
- केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग से निधि जारी करने के लिए कुछ सांसदों ने उठाई आवाज

अरविंद मिश्र, भोपाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के कुछ महीनों के भीतर ही सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया था। योजना के तहत 2014 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से सांसदों को तीन गांव गोद लेने थे और 2019 से 2024 के बीच पांच गांव गोद लेने की बात कही गई है। लेकिन अपने क्षेत्र में विकास के बड़े-बड़े वादे करने वाले सांसदों ने इसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। इस कारण सांसदों के गोद लिए गांव भी विकास के लिए तरस रहे हैं। अगर यह कहा जाए की फंड के अभाव में सांसदों के गोद लिए गांव 'लावारिस' हो गए हैं तो इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में 16 मार्च 2021 को दिए एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी सामने आई है कि पिछले 6 साल में देश भर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 77,457 परियोजनाएं शुरू की गई थी जिनमें से 63.25 फीसदी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अगर मप्र की बात करें तो यहां के 101 गांवों में संचालित 2,828 परियोजनाओं में से 1,894 यानी 66.9 प्रतिशत ही पूरी हो सकी हैं। ऐसे में गांवों में विकास आधे-अधूरे हैं।

1,753 गांवों में 77,457 परियोजनाएं

देश भर में चयनित ग्रामों में 77,457 परियोजनाएं शुरू की गई थी जिनमें से 11 मार्च 2021 तक जारी आंकड़ों के अनुसार 63.25 फीसदी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्यवार आंकड़ों को देखें तो पश्चिम बंगाल में 61 परियोजनाएं ही शुरू की गई थी। देश में सबसे सफल राज्य तमिलनाडु है जहां शुरू की गई 5,897 परियोजनाओं में से 91.5 फीसदी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। यूपी में 90.9, गुजरात में 77.3, कर्नाटक में 76.3, उत्तराखंड में 73.8, छत्तीसगढ़ में 71.1, मिजोरम में 70 फीसदी, मध्य प्रदेश में 66.9, हरियाणा में 66.8, सिक्किम में 62.7 और केरल में 62.4 फीसदी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मेघालय में सिर्फ 25.7 फीसदी परियोजनाएं ही पूरी हुई हैं।

मध्यप्रदेश फीसड्डी

मप्र में लोकसभा के 29 और राज्यसभा के 11 सांसद हैं। इनमें से लोकसभा के 28 और राज्यसभा के 8 सांसद भाजपा के हैं। यानी 40 में से 36 सांसद भाजपा के हैं, लेकिन इनमें से मात्र 7 सांसदों ने ही आदर्श ग्राम योजना के चौथे चरण में गांवों को गोद लिया है। इस कारण मप्र बड़े राज्यों में फीसड्डी साबित हुआ है। मप्र के सांसदों ने पांच चरणों में कुल 101 गांवों को गोद लिया है।

इनमें सबसे कम चौथे चरण में अब तक मात्र 7 गांवों को गोद लिया है। जबकि चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 52, तमिलनाडु के 36, महाराष्ट्र के 32, गुजरात के 28, राजस्थान के 20, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के सांसदों ने 9-9 गांवों को गोद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल सांसद आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के सांसदों की रुचि नहीं दिखाई दे रही है।

40 मध्यप्रदेश के सांसद

36 भाजपा के सांसद

101 गांवों को लिया गोद

अब तक 2046 गांवों को लिया गोद

11 मार्च 2021 तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,046 ग्राम पंचायतों को गोद लिया जा चुका है। देश भर में अब तक सबसे ज्यादा उत्तरप्रदेश में 361 गांवों को गोद लिया गया है। इसके बाद तमिलनाडु में 203, महाराष्ट्र में 179, गुजरात में 129, राजस्थान में 120, आंध्र प्रदेश में 110, केरल में 104 और फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है जहां 101 गांवों को गोद लिया गया है।

गांव गोद लेने के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कलेक्टरों से इस दिशा में प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया है। एसएजीवाई के तहत हर लोकसभा सदस्य को अपने क्षेत्र का एक गांव गोद लेना है। उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उसके विकास पर ध्यान रखना है।

डॉ. आशीष सक्सेना, उप निदेशक, नीति, योजना एवं निगरानी, ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रदेश के गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार तत्पर रही है। बेहतर नीति और सही नीयत से ही गांव, प्रदेश और देश का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने गांव के विकास के द्वार खोल दिए हैं। इस योजना में 6 राज्यों के चुनिंदा जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। इनमें हरदा, सीहोर और डिंडोरी सम्मिलित हैं। इस योजना द्वारा गांव के विकास के द्वार खुल गए हैं। आज गांव-गांव विकास की गंगा बहाई जा रही है। लोगों को अब किसी काम के लिए भटना नहीं पड़ता है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

2024 तक 8 गांवों का विकास

केंद्र ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के आंकलन के लिए एक साझा समीक्षा मिशन गठित किया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का गांवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है न ही इनके उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ऐसे में इस रिपोर्ट में योजना की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। योजना में 2016 तक प्रत्येक सांसद को एक-एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करना था। 2019 तक दो और गांवों और 2024 तक आठ गांवों का विकास किया जाना था।

देश का पहला गौ-अभ्यारण्य निजी हाथों में देगी सरकार!

» आरएसएस के ड्रीम प्रोजेक्ट से राज्य सरकार खींचेगी हाथ

» लोकार्पण में ही सरकार ने लगाया था 5 साल का समय

» अब गायों के खाने-पीने और इलाज की व्यवस्था नहीं

संवाददाता, भोपाल

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से देशभर में प्रदेश का नाम चर्चित हो चुका है, उससे ही अब प्रदेश भाजपा की सरकार ने हाथ खींचने की तैयारी कर ली है। यह प्रोजेक्ट है सुसनेर का गौ अभ्यारण। इसका निर्माण बीते कार्यकाल में शिवराज सरकार ने ही संघ द्वारा की गई पहल पर कराया था। इसे प्रदेश का सबसे बड़ा गौ-अभ्यारण्य होने का दर्जा मिला है। संघ के लिए इस प्रोजेक्ट के महत्व को इससे ही समझा जा सकता है कि इस अभ्यारण्य के 24 दिसंबर 2012 को हुए भूमिपूजन में स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित हुए थे।

दरअसल, इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरू से ही सरकार कितनी उदासीन रही है इससे ही समझा जा सकता है कि इसके पूरे होने में लगभग पांच साल का समय लगा दिया गया। इसकी वजह से इसका लोकार्पण 7 सितंबर 2017 को हो सका। इस कार्यक्रम में भी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। अब लोकार्पण के तीन वर्ष बाद ही संघ की इस महत्वाकांक्षी योजना से सरकार ने पूरी तरह से हाथ खींचने की तैयारी करते हुए इसे निजी हाथों में देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में निजी गौ-शालाओं की दुर्दशा किसी से भी छिपी नहीं है, जिसकी वजह से अब इस गौ-अभ्यारण्य के भविष्य पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं।

निजी संचालकों द्वारा गौ-शालाओं में गौ-माता का संरक्षण और संवर्धन करने की जगह उनका दोहन किया जाता है। इनमें जब तक गाय दूध देती है, तब तक तो उसकी पूरी देखभाल की जाती है, लेकिन उसके बाद उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी अकाल मौत हो जाती है। खास बात यह है कि दूध बंद होते ही उन्हें भोजन पानी तक नहीं दिया जाता है। बीमार होने पर इलाज की बात तो सोची ही नहीं जाती है।

फाइल फोटो

6000 गायों की क्षमता

50 करोड़ रुपए खर्च

1100 एकड़ में अभ्यारण्य

कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी

मप्र गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश कर उस पर मंजूरी ली जाएगी। इसके लिए तीन निजी फर्मों ने दिलचस्पी दिखाई है। अब अंतिम निर्णय कैबिनेट को ही करना है।

अभ्यारण्य की खासियत

सुसनेर के गौ-अभ्यारण्य में 6000 गाय रखने की क्षमता है। परिसर में खुला और प्राकृतिक वातावरण भी मौजूद है। इस अभ्यारण्य के निर्माण में उस समय 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी।

सीएम दे चुके सहमति

मप्र गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा तैयार किए गए निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर पूर्व में एक बड़ी बैठक हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी बोर्ड के प्रस्ताव पर सहमति दी जा चुकी है।

1100 एकड़ में गौ-अभ्यारण्य

दरअसल, 1100 एकड़ क्षेत्र में फैले इस गौ-अभ्यारण्य को बदइंतजामी के वजह से सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी है।

दम तोड़ रहीं गाय

अभ्यारण्य में बदइंतजामी का आलम यह है कि यहां लगातार गायों की मौत हो रही है। यही नहीं, यह अब तो पशुओं के बीमार होने और उन्हें ठीक से चारा और पानी नहीं मिलने की लगातार शिकायतें मिलने की वजह से बदनाम हो चुका है।

देश का पहले गौ-अभ्यारण्य

सुसनेर के सालरिया गांव स्थित गो अभ्यारण्य देश का पहला गौ अभ्यारण्य है। सरकार ने 2012 में 472 हेक्टेयर क्षेत्र में कामधेनु गौ अभ्यारण्य अनुसंधान और उत्पादन केन्द्र का भूमिपूजन किया था। सितंबर 2017 में इसका शुभारंभ किया गया था।

वैज्ञानिक बनाते दवाइयां

प्रदेश के इस पहले अभ्यारण्य को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई थीं। यहां गौ-मूत्र से दवाइयां बनाने दावा किया गया था। गोबर से गैस बनाने के साथ कई प्रयोगों की शुरुआत होनी थी। यही नहीं गौ-मूत्र और गोबर पर रिसर्च भी शुरू की जानी थी।

एक गांव ऐसा जहां आज भी झोपड़ी में चल रही पाठशाला

» आजादी के 75 साल बाद भी न मिली पक्की सड़क और न ही बिजली

» केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय जिला श्योपुर की कहानी

» जिम्मेदार गांवों की सूरत बदलने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे

संवाददाता, भोपाल

देश को आजाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए हैं। इस दौरान रोटी-कपड़ा-मकान के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए बड़े-बड़े दाबे किए गए हैं। लेकिन विसंगति यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र के जिले श्योपुर के एक गांव में आज भी झोपड़ी में पाठशाला चल रही है।

गांव में न सड़क है न बिजली है और न ही पीने का पानी है। फिर भी जिम्मेदार क्षेत्र के गांवों की सूरत बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इससे केंद्रीय मंत्री के जिले में शासन की योजनाओं को पलीता लग रहा है। दरअसल, श्योपुर जिले के वनांचल क्षेत्र में खूटका गांव का है।

जहां स्थिति यह है कि, गांव में न बिजली है और नहीं पक्की सड़क, आवास और पीने के पानी के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। इससे यहां के रहवासियों को गांव की पहाड़ी से नीचे उतरकर नदी से पीने का पानी लाना पड़ता है। गर्मियों के सीजन में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इससे परेशान ग्रामीणों को घरों पर ताला लगाकर पलायन करने की नौबत का सामना तक करना पड़ता है।

अनूप ने दिया था आश्वासन

मुरैना-श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद अनूप मिश्रा ने जिले के दौरे के दौरान खूटका गांव में झोपड़ियां देखकर हालातों के बारे में जानकारी ली गई थी। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया था कि गांव की तस्वीर बदली जाएगी। लेकिन हालात जस के तस हैं। गांव में एक भी पक्का मकान, पक्की सड़क, बिजली आदि के इंतजाम हैं और तो और गांव का सरकारी स्कूल भी घास की झोंपड़ी में संचालित हो रहा है।

किसी ने नहीं ली सुध

इधर, खूटका गांव के उप सरपंच पोकर मारबाड़ी का कहना है कि कई सरकारें बदल गईं, लेकिन हमारे गांव में रत्ती भर भी विकास नहीं हो सका है। गांव में बिजली, सड़क आवास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। वहीं खूटका गांव के मेवाराम गुर्जर का कहना है कि पहले अनूप मिश्रा सांसद थे, तब उन्होंने हमारे गांव में विकास कराने का बादा किया था लेकिन, उनका कार्यकाल होने के बाद अभी तक हमारी किसी ने सुध नहीं ली है।

यह बात सही है कि खूटका गांव में पक्की सड़क और बिजली की कमी है। गांव में एक भी पक्का आवास नहीं है, लेकिन हम जल्द ही वहां सभी सुविधाएं मुहैया कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह क्षेत्र वन रेंज में आता है। इसलिए पहले यहां के रहवासियों को विस्थापित किया जाएगा। तभी ये गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा।

सीताराम आदिवासी, भाजपा विधायक विजयपुर

बंजर भूमि में अब 'सोना' उगाएंगे किसान

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 15 साल से चल रहे केन बेतवा लिंक परियोजना से पानी लेने का विवाद सुलझ गया है। परियोजना से नंवबर से अप्रैल के बीच में मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। 35,111 करोड़ की लागत की इस परियोजना में 90 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी। जबकि शेष 5-5 फीसदी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश वहन करेंगे। इससे मप्र के नौ जिलों को पानी मिलेगा। सूखे की मार झेलने वाले बुंदेलखंड के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना वरदान से कम नहीं है। इससे नौ जिलों में हरियाली के साथ-साथ किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी आएगी। 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी, जिसका सीधा असर

उत्पादन पर पड़ेगा। किसान दो से तीन फसलें ले पाएंगे। इससे न सिर्फ उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पेयजल संकट से भी क्षेत्र को निजात मिलेगी।

परियोजना के दायरे में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले आएंगे। बुंदेलखंड के जिलों में पानी की बड़ी समस्या है। जबकि महाकोशल, मालवा और निमाड़ क्षेत्र के किसान सालभर में दो या तीन फसलें ले रहे हैं। परियोजना से सिंचाई क्षमता का जो विस्तार होगा, उससे किसानों के चेहरों पर खुशहाली आएगी। पानी की उपलब्धता से ग्रीष्मकालीन फसलें होंगी, जो किसानों को आर्थिक तौर पर समृद्ध करेगी।

केन बेतवा परियाजेना से बुंदेलखंड में खुशहाली

- प्रदेश के नौ जिलों में 8.11 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई
- अन्नदाताओं के आए अच्छे दिन, दो और तीन फसल ले सकेंगे
- पीएम मोदी की मौजूदगी में शिवराज-योगी के बीच पानी के बंटवारे को लेकर समझौते पर हुए हस्ताक्षर
- 35,111 करोड़ के प्रोजेक्ट में 90 फीसदी राशि केंद्र और 5-5 प्रतिशत हिस्सेदारी मप्र-यूपी वहन करेंगे
- केन-बेतवा लिंक परियोजना में दो बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावाट

दूसरे राज्य से आने वालों की पंचायत में बनेगी 'कुंडली'

भोपाल। मप्र में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़ों पर गौर करें, तो इस बार संक्रमण की रफ्तार ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से बढ़ने लगी है। इसी के चलते सरकार द्वारा यहां भी अलर्ट घोषित किया है। इसे लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि, सभी पंचायतों में प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जाए। राज्य के बाहर से आने वालों की कोरोना की जांच रिपोर्ट देखी जाएगी।

शहर के साथ गांवा पहुंचा कोरोना अलर्ट

इसी आधार पर आने वाले को प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की जांच नहीं हुई होगी, तो तत्काल उसकी सूचना पास के स्वास्थ्य केंद्र, जनपद या जिले के नोडल अधिकारी को दी जाएगी। पंचायतें यह तय करेंगी कि अन्य प्रदेशों से गांव लौटने वालों की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज हो और जांच कराई जाए।

कुकिंग यूज ऑयल से चलेंगी गाड़ियां

अनूठी पहलः पकौड़े-समोसे तलने के बाद बचे तेल बनेगा बायो डीजल

- प्रदेश के डेढ़ दर्जन जिलों की रेस्टोरेंट, होटलों से करेंगे खरीदी
- कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल से होती हैं गंभीर बीमारियां
- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम-हिंदुस्तान को मिला जिम्मा
- इंदौर में लगेगा प्रदेश का पहला 30 टन उत्पादन का संयंत्र

संवाददाता, भोपाल

दुकानों पर पकौड़े, कचौरी या अन्य खान-पान की चीजें तलने के बाद बचे तेल का फिर से उपयोग करना आम बात है, जबकि ये सेहत के लिए खतरनाक है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मप्र सरकार जल्द ही एक अनूठी पहल करने जा रहा है। जी हां, इस्तेमाल हो चुके कुकिंग ऑयल से बायो डीजल बनाया जाएगा। जिससे गाड़ियां भी चलेंगी। गौरतलब है कि देश के साथ ही मप्र में भी पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल मप्र में मिल रहा है। भोपाल की बात की जाए तो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसी तरह डीजल भी 100 रुपए लीटर के करीब पहुंच गया है। वहीं एलपीजी का 14 किलो का गैस सिलेंडर 850 रुपए में मिल रहा है। दरअसल, भोपाल सहित प्रदेश में बड़े-बड़े रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों में खाद्य सामग्री बनाने के बाद हमेशा तेल बच जाता है। अब जल्द ही खाद्य फैक्ट्रियों और होटलों की यह परेशानी खत्म होने वाली है। अब उपयोग किए गए खाद्य तेल से बायो डीजल बनाया जाएगा। इस संबंध में हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में यह सामने आया है कि बायो डीजल प्लांट के लिए रोजाना 40 टन जले हुए खाद्य तेल की जरूरत होगी। हालांकि वर्तमान में सिर्फ भोपाल में ही यूज कुकिंग ऑयल खरीदा जा रहा है।

भोपाल में जमा कर रहे तेल

भोपाल में ईट राईट चैलेंज के तहत उपयोग किए गए खाद्य तेल को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए एक निजी कंपनी आगे आई है। कंपनी 30 रुपए लीटर उपयोग किया हुआ तेल खरीद रही है। जनवरी तक 2100 लीटर से अधिक तेल जमा किया गया था। उपयोग किए गए खाद्य तेल को लेकर शुरू किए अभियान के तहत कई एजेंसियां खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नहीं दिल्ली द्वारा अधिकृत की गई है।

इंदौर में बनेगा तेल संग्रहण केंद्र

इंदौर शहर के पास भी फरसपुर गांव में बायो डीजल संयंत्र और पास में ही तेल संग्रहण केंद्र बनाया जा रहा है। इंदौर के 200 किमी के दायरे में आने वाले 16 जिलों के नमकीन उद्योग, रेस्त्रां और होटलों का अनुपयोगी खाद्य तेल जुटाया जाएगा। इनमें इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, भोपाल, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, खंडवा, खरगोन आदि शामिल हैं।

देश में हर साल बनेगा 110 करोड़ लीटर बायो डीजल

भारत में हर साल 2,700 करोड़ लीटर कुकिंग ऑइल का इस्तेमाल होता है, जिसमें से 140 करोड़ का होटल्स, रेस्त्रां और कैंटीन से एकत्र किया जा सकता है। इनसे हर साल करीब 110 करोड़ लीटर बायो डीजल बनाया जाएगा। इस समय यूसीओको कलेक्ट करने के लिए कोई चेन नहीं है।

इंदौर में पहला संयंत्र होगा

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आईओसी के साथ यह पहल की है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु आदि में 14 स्थानों पर इस तरह के बायो डीजल संयंत्र हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी तरह का यह पहला संयंत्र होगा।

इनका कहना है

शासन की ओर से बायो डीजल नीति बनाई गई है। इसमें रियूज कुकिंग ऑयल से बायो डीजल बनाने को प्राथमिकता दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 100 टन तक उपयोग किया गया कुकिंग ऑयल जमा करें।

तरुण पिथौड़े, एमडी, संचालक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

कुकिंग ऑयल के अलावा बायो डीजल कई रूपों में उपलब्ध है। यह व्यर्थ से धन में परिवर्तन है। हम बायोफ्यूल डे को वैकल्पिक ऊर्जा दिवस के रूप में मनाएंगे। इस्तेमाल हो चुके तेल को दोबारा खाने में इस्तेमाल से कई बीमारियां होती हैं।

धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

इंदौर के लिए बायो डीजल बनाने वाली दो-तीन कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट- शुरुआती सहमति पत्र दिया है। एक कंपनी आगे आई है। हम उनसे 10 साल के लिए बायो डीजल खरीदेंगे।

■ **पीसी गुप्ता,** उप महाप्रबंधक, आईओसी के रिन्यूएबल एनर्जी विभाग, दिल्ली

हमें उम्मीद है कि मप्र के16 जिलों से 40 टन तेल की पूर्ति आराम से हो जाएगी। हम नमकीन और चिप्स निर्माताओं से लगातार संपर्क में हैं। चयनित जिलों में कुकिंग ऑयल भारी मात्रा में बचता है।

■ **विजय ओसवाल,** डायरेक्टर, तेल एकत्रित करने वाली एमजी रिन्यूएबल एनर्जी

खाने के किसी भी तेल को तीन बार से अधिक गर्म करने पर यह स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाता है। भारत सरकार की बायो डीजल नीति में रियूज कुकिंग ऑयल से बायो डीजल के निर्माण को शामिल किया गया है।

■ **अरविंद पथरौल,** खाद्य सुरक्षा के राज्य नोडल अधिकारी

शासन की ओर से बायो डीजल नीति बनाई गई है। इसमें रियूज कुकिंग ऑरूल से बायो डीजल बनाने को प्राथमिकता दी गई है। एफएसएसएआई इसमें समन्वयक की भूमिका में है। बायो डीजल से जब गाड़िया चलेंगी तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा।

■ **अभिषेक दुबे,** संयुक्त नियंत्रक, खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग

प्रदेश की प्रगति का आधार-ग्रामीण विकास

महेंद्र सिंह सिसोदिया
पंचायत मंत्री, मप्र

खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।

जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर ही रह जाते हैं, जिंदगी में वही कामयाबी पाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इस सूत्र वाक्य को जिसने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया वह यशस्वी कहलाया। हम मध्यप्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि हमें खामोशी से काम करने वाला ऐसा ही एक योद्धा मिला है- शिवराज सिंह चौहान के रूप में। मैं अपने आपको भी बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे कर्मयोद्धा के नेतृत्व में मुझे काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं हृदय से आभारी हूं कि मुख्यमंत्री ने मुझे पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा। सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारी सरकार का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र के सहारे हम प्रदेश की जनता की सेवा के महान कार्य में जी-जान से जुटे हुए हैं। सफलता की ऊंची पायदान पर विराजमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने उपलब्धियों के अनेक परचम फहराए हैं। इनकी बात हम सप्रमाण बाद में करेंगे। पहले उन विशिष्ट उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, जहां मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मेहनत और लगन से काम करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सड़कें प्रगति का प्रतीक हैं और देश और प्रदेश की तरक्की में इनका विशेष योगदान है। प्रतिशत लेंथ एचीवमेंट में प्रदेश का स्थान पहला है। प्रदेश में 2550 किमी के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2603 किमी लंबाई के मार्गों का निर्माण किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की समग्र रैंकिंग में भी मप्र को प्रथम रैंक मिली है। मनरेगा के बारे में हमें यह बताते हुए हर्ष होता है कि प्रति परिवार औसत मानव दिवस सृजन में हम देश में प्रथम हैं। कोविड काल में मनरेगा के अंतर्गत सृजित मानव दिवस योजना प्रारंभ से अब तक मध्यप्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक रहा है। प्रदेश में अब तक 54 लाख 29 हजार जॉब कार्डधारी परिवारों के एक करोड़ 29 लाख श्रमिकों द्वारा 32 करोड़ 79 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अनुचित जाति-जनजाति के परिवारों को रोजगार देने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर हैं। प्रदेश में इस वर्ष कोविड के दौरान भी प्रति दिवस 25 लाख से अधिक का श्रमिक नियोजन किया गया, जो देश में सर्वाधिक श्रमिक नियोजन है। हर आदमी को घर देने के लिए कृत-संकल्पित प्रधानमंत्री की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में भी मध्यप्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में सफलता के नये सोपान रचे हैं। स्वीकृति की तुलना में निर्मित आवास के प्रतिशत को देखा जाये, तो यहां भी मप्र पहली पायदान पर खड़ा नजर आएगा। प्रदेश में अब तक 25 लाख स्वीकृत घरों में 18 लाख 30 हजार आवास बनाए जा चुके हैं। ग्रामीणों को रोजगार देने की प्रक्रिया में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महती भूमिका है। इसके अंतर्गत काम कर रहे स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज के लिए प्रकरण प्रस्तुत करने में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अब तक एक लाख दो हजार 765 समूहों के 2 हजार 609 करोड़ 18 लाख प्रकरण बैंक में प्रेषित किए गए हैं। बैंक द्वारा स्व-सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने में देश में हम प्रथम हैं। अब तक 45 हजार 498 प्रकरण स्वीकृत कर एक हजार 161 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। प्रदेश में 23 हजार 458 ग्रामों में कृषि गतिविधियां महिलाएं संचालित कर रही हैं। प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम में 13 हजार 111 उद्यम गठित कर प्रदेश ने देश में प्रथम रैंक प्राप्त की है। प्रदेश में सबसे अधिक 46 सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। जब प्रदेश का मुखिया खुद किसान हो और जो किसान हितैषी के रूप में चर्चित हो, उसके राज्य में सिंचाई योजना में उपलब्धियां तो मिलना ही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटर शेड विकास के संदर्भ में जल-संग्रहण संरचनाओं के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इस वर्ष प्रदेश में 5 हजार 256 जल-संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। सिंचाई सामर्थ्य विकास में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। कुल 21 हजार 719 सिंचाई सामर्थ्य इस साल विकसित की गई है। तीस लाख 16 हजार मानव दिवस अर्जित कर प्रदेश इस मामले में भी सबसे ऊपर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन में मप्र पहला राज्य है, जिसने मिशन के अंतर्गत समस्त कार्यों को प्रारंभ से लेकर पूर्ण होने तक के पड़ावों को जियो-टैग्ड किया है। इसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। ग्रामीण पथ-विक्रेता ऋण योजना प्रदेश की अनूठी योजना है, जो भारत वर्ष के अन्य प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं है। इसके तहत अब तक एक लाख 71 हजार पथ-विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए का ब्याज-रहित ऋण दिया गया है। मनरेगा में मजदूरों को नवीन जॉब-कार्ड से जोड़ने में प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। वित्तीय प्रगति के मापदंड के अनुसार इस वर्ष मध्यप्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। यह प्रगति वॉटर-शेड विकास में हुई है। इसी योजना में लाभान्वित कृषक परिवारों के संदर्भ में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत 282 किचन-शेड कम डायनिंग हॉल के कार्य प्रगति पर हैं। इस मद में कुल राशि 20 करोड़ 30 लाख रूपए है, जिसमें मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की राशि 31 लाख 90 हजार रुपए तथा मनरेगा अभिसरण की राशि 11 करोड़ 50 लाख रुपए है। इसके चलते अब प्रदेश की शालाओं में छात्र-छात्राएं जमीन पर बैठकर नहीं, बल्कि डायनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करेंगे। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हम प्रदेश की जनता को सर्वोच्च स्थान देते हैं और मानते हैं कि हम जो कुछ भी उपलब्धि हासिल कर पाए हैं, वह जनता के सहयोग और भागीदारी से ही संभव है। इसी के चलते हमारे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर न केवल सराहा गया, बल्कि पुरस्कृत भी किया गया। मनरेगा के अंतर्गत खंडवा जिले की कावेरी नदी के पुनर्जीवन के लिए मध्यप्रदेश को नेशनल वॉटर अवार्ड में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह नीमच जिले की बोरखेड़ी नदी पुनर्जीवन के लिये तृतीय पुरस्कार भी हमें प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वॉटर-शेड विकास के अंतर्गत सागर- जल-संरक्षण में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

> जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर ही रह जाते हैं, जिंदगी में वही कामयाबी पाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इस सूत्र वाक्य को जिसने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया वह यशस्वी कहलाया। हम मध्यप्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि हमें खामोशी से काम करने वाला ऐसा ही एक योद्धा मिला है- शिवराज सिंह चौहान के रूप में।

सोशल डिस्टेंसिंग 'होली'

गरिमा राय

होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगो में रंग मिल जाते है...रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे..होली आयी होली आयी आदि गीतों को टोली में हुड़दंग मचाते हुए गाए बगैर..दोस्तों को गले लगाए बगैर..गुजिया मोहल्ले के साथ खाए बगैर...भला होली मनाई है कभी हम सब ने मगर इस साल बगैर दोस्तों की टोली के होली मनाना है।

गत वर्ष होली के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि वे किसी होली उत्सव में शामिल नहीं होंगे। यही घोषणा भारत के आम जनता के लिए कोरोना महामारी की दस्तक थी। जिसे हम सब ने गंभीरता से नहीं लिया था। परिणाम स्वरूप 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। जिससे सबका जीवन अस्त व्यस्त हुआ,जिसकी यहां चर्चा करना व्यर्थ है। सबके लिए 2020 वर्ष मनहूस, दुखदाई व परेशानियों भरा ही सबित हुआ।

फिर कुछ समय बाद कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई, लड़खड़ाई अर्थवयवस्था प्रकट हुई। सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट देनी शुरू की फिर कुछ दिशा-निर्देश के साथ लॉकडाउन हटा दिया। स्थिति सामान्य हो ही रही थी पर हमने अपनी लापरवाहियों से फिर कोरोना की रफ्तार तेज कर दी।

कोरोना का मुकाबला हम सबको एकजुटता और सयंमता के साथ करना होगा। माना कोरोना के दिशा-निर्देश जैसे मास्क लगाना सेनिटाइज करना आदि चिड़चिड़ाहट और उक्ताहट लाते हैं, कठिन हैं उबाऊ हैं पर समस्या भी विषम है, इसलिए समस्या का उपाय कितना भी झंझट वाला लगे हमें उसका पालन तो करना होगा। जिस तरह हम सब व्रत उपवास करते हैं अपने खाने-पीने की लालसा में सयंम प्रदर्शित करते हैं उसी तरह हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई, अपनी इच्छाओं में सयंम रख कर जीतनी होगी। हमें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा वरना अगली होली भी बिना 'रंग बरसे', मित्रों के बगैर गुजिया खाकर बिताना होगा।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है सामाजिक दूरी उसके लिए कठिन है पर इसी दूरी से हम कोरोना महामारी को दूर कर पाएंगे। टीकाकरण का काम तेजी से शुरू हो गया है। ये सरकार का सराहनीय कदम है पर वर्तमान में टीकाकरण को सफल मान लेना जल्दबाजी होगी। अत: हमें टीकाकरण के बावजूद सावधानियां बरतनी होंगी।

पिछली होली में हम सबने कोरोना की दस्तक को नजरअंदाज किया, कम से कम इस होली में हम सब संकल्प लें कि सरकार द्वारा जो दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पूरा ईमानदारी से पालन करेंगे। अपनी इच्छाओं पर सयंम रखेंगे एवं एकजुटता के साथ कोरोना को पराजित करेंगे। इसी विश्वास के साथ कि अगले वर्ष होली हम सब खुलकर खेलेंगे। रंग बरसे गाएंगे, मोहल्ले में सबके साथ गुजिया खाएगे, मित्रों के साथ टोली में हुरदंग करेंगे। आइए इसी आशा के साथ हम सब एक दूसरे को होली की शुभकामनाए दें।

कोरोना कालः ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश

डॉ. मोहन यादव
उच्च शिक्षा मंत्री, मप्र

राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। कोरोना के संकट के बावजूद भी ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों को पठन-पाठन से जोड़े रखा गया। ओपन बुक प्रणाली से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित कराने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना। बाद में इसका अनुसरण पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों ने भी किया। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए साहित्य, विज्ञान, उद्योग, वाणिज्य, कृषि आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छानुसार जुलाई-2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत 20 घटकों के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अकादमिक गुणात्मक एवं उन्नयन संबंधी कार्रवाई की गई है। इसमें भवन निर्माण, स्मार्ट क्लॉस-रूम एवं वर्चुअल लर्निंग सुविधा, एकीकृत पोर्टल का निर्माण, सूचना तकनीक को सुदृढ़ बनाना, महाविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, उद्यमिता प्रकोष्ठों का गठन आदि को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सतत रूप से समीक्षा की जा रही है। रणनीति बनाकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। महाविद्यालयों के विकास के लिए जन-भागीदारी मद से 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की सीमा तय की जा रही है। इस मद में दान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यदि कोई दानदाता पांच लाख रुपए या इससे अधिक राशि दान करता है, तो उसे मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। पिछले एक साल में 44 नवीन अशासकीय महाविद्यालय एवं 4 नवीन निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन के लिए 263 लाख की राशि से 18 महाविद्यालय तथा पुस्तकालय विकास के अंतर्गत 192 लाख की राशि से 25 महाविद्यालयों को उन्नत किया गया है। महाविद्यालय विकास योजनाओं के अधीन 96 करोड़ की राशि से चल रहे 117 कार्यों में से 14 भवनों का कार्य पूर्ण किया गया है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं की संचालन व्यवस्था के अंतर्गत यू-ट्यूब के माध्यम से 1200 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित ऑडियो/वीडियो व्याख्यान उपलब्ध कराए गए।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर करीब 14 लाख 58 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए। ओपन-बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से 18 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना में अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण का लाभ शासकीय महाविद्यालयों के करीब 19 हजार विद्यार्थियों ने लिया। नियोजन तथा उद्यमिता प्रकोष्ठों के गठन के लिये 200 महाविद्यालयों का चयन एवं ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तक एवं स्टेशनरी वितरण योजना से 97 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। विश्व बैंक परियोजना से 260 करोड़ की राशि से 20 भवनों का निर्माण पूरा किया गया। रूसा, विश्व बैंक परियोजना एवं राज्य मद से निर्मित 29 महाविद्यालयों के भवनों का लोकार्पण हुआ। इन महाविद्यालय भवनों में आवश्यक सुविधाओं के लिए 767 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। राज्य शासन की मद से 9 महाविद्यालयों के भवन निर्माण, 73 महाविद्यालयों में 600 अध्ययन कक्ष और 45 नवीन भवनों के निर्माण के लिये 206 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रोत्साहन देने के लिए 136 महाविद्यालयों में गुणवत्ता अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिए उच्च शिक्षा विभाग और मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू किया गया।

■ गुना और टीकमगढ़ के माझी दंपती के जुनून-जज्बे की कहानी

■ बगिया में आम, अमरूद, आंवला, नींबू और पपीता के पौधे लगे

कुछ कर गुजरने का जुनून और न हारने की जिद, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इन दो शब्दों को उतार लिया वह नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इसी तरह के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार के दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। **'जागत गांव हमार'** अपने इस अंक में मांझी की तरह ही मध्यप्रदेश में भी कुछ ऐसे दंपतियों के बारे में बता रहा, जिन्होंने पत्नी और पेड़ों से प्रेम के चलते अपने जुनून से समाज में एक मिसाल कायम की है। दरअसल, गुना जिले के भारत अपनी पत्नी को रोज-रोज परेशान होते देख रहे थे। एक दिन पत्नी बहुत उदास हो गई। तब उन्होंने खुद का एक कुआं खोदने की ठानी। इसी तरह टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव के पचिया ने अपने पति हरिराम के साथ मिलकर सात साल तक पहाड़ काटकर कुआं खोदा और बंजर जमीन पर अपना बगीचा तैयार कर लिया।

एक ने पत्नी के लिए कुआं तो दूसरे ने पेड़ों के प्रेम खोदा पहाड़

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश के गुना जिले के भानपुरा बाबा गांव के भारत सिंह मेर की पत्नी आधा किमी दूर हैंडपंप पर पानी भरने जाती थी, उसकी रोज की यह मशक्कत उनसे देखी नहीं गई। 46 साल के भारत सिंह ने घर पर ही 31 फीट गहरा कुआं खोद दिया। मेर के इस प्रेम को देखकर जिले के कलेक्टर ने भी उन्हें सलाम किया है। दरअसल, भारत सिंह की पत्नी सुशीला बाई जिस हैंडपंप पर जाती थीं, उसकी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अक्सर उसकी चेन टूट जाती थी। सुशीला बाई बार-बार इससे परेशान होतीं और कभी-कभी तो उन्हें बिना पानी लिए ही लौटना पड़ता था। यह बात भारत सिंह के मन में इतनी गहरी बैठी कि दो महीने पहले घर के बाहर कुआं खोदने की ठान ली। भारत सिंह ने 15 दिन में 31 फीट गहरा और साढ़े चार फीट चौड़ा कुआं खोद दिया। इतना ही नहीं, एक महीने में उसे पक्का कर आधा बीघा जमीन की सिंचाई भी कर डाली।

किस्मत वालों को मिलता है ऐसा पति

भारत सिंह ने बताया कि पहले दिन जब मैंने कुआं खोदने के लिए गैती और फावड़ा चलाया तो सुशीला मजाक उड़ाने लगी। पत्नी का कहना था कि मैं कुआं नहीं खोद पाऊंगा, उसके इस परिहास ने मेरे निर्णय को और मजबूत कर दिया। पांच दिन के भीतर ही करीब 15 फीट तक खोदाई कर दी। अब सुशीला कहती हैं कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा प्रेम करने वाला पति किस्मत वालों को ही मिलता है।

कलेक्टर बोले-दिलाऊंगा पीएम आवास

जिले की यह पहली घटना है कि किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए अकेले ही कुआं खोद डाला। कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने कहा कि भारत सिंह और उसकी पत्नी को पीएम आवास दिलाया जाएगा। साथ ही शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। भारत सिंह की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

बंधुआ मजदूरी से मिली आजादी वीरान जमीन में अब फलदार पेड़ों की दिख रही हरियाली

इधर, टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव में रहने वाली पचिया अहिरवार ने अपने पति हरिराम अहिरवार के साथ मिलकर सात साल तक पहाड़ काटकर कुआं खोदा और बंजर जमीन पर अपना बगीचा तैयार कर लिया। अब इसी कुंए के पानी से दंपती बगीचे की सिंचाई करते हैं। साथ ही इसी बगीचे से उनकी आजीविका भी चलती है। हरिराम का कहना है कि यह सब कुछ उनकी पत्नी के कारण ही संभव हुआ है। बुजुर्ग दंपती ने कई साल तक बंधुआ मजदूरी की, लेकिन बाद में उससे आजाद हो गए, ऐसे में उन्हें आजीविका चलाने में परेशानी होने लगी। दंपती के पास दो एकड़ बंजर जमीन थी, जो कई साल से वीरान पड़ी रहती थी। इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए दोनों ने कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए अधिकारियों के हाथ जोड़े, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। इससे तंग आकर पचिया ने अपने पति को कुआं खोदने के लिए कहा, पत्नी से प्रेरणा लेकर हरिराम ने पहाड़ काटकर कुआं खोदने की शुरुआत की। सात साल तक 20 फीट खुदाई करने के बाद दोनों ने पत्थरों से पानी निकाल लिया। पानी मिलने के बाद दोनों ने बंजर जमीन पर बगिया लगाई और उसे हरा-भरा कर दिया।

बगिया से गुजारा

पचिया अहिरवार बताती हैं सरकारी मदद नहीं मिलने पर हमने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई और कुआं खोदने में जुट गए। पानी मिलने के बाद हमने दो एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ बना लिया। अब हमारी बगिया में आम, अमरूद, आंवला, नींबू और पपीता सहित कई फलदार पौधे लगे हैं। इसी से परिवार का गुजारा चलता है।

अब चारों ओर हरियाली : कुछ साल पहले तक इस भूमि पर कुछ नहीं होता था। मेहनत के कारण अब यहां हरियाली है, बंजर जमीन पर यहां चारों सिर्फ फलदार पेड़ नजर आते हैं। दंपती की इस मेहनत की इलाके के लोग मिसाल देते हैं।

■ देश में ऐसा फैसला करने वाला होगा पहला राज्य होगा अपना एमपी

■ मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में बड़ा कदम

■ विधेयक का मसौदा तैयार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लेंगे अंतिम निर्णय

प्रदेश में पौधरोपण को मिलेगा फसल का दर्जा

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने और पौधारोपण को प्रोत्साहित करने की दिशा में नवाचार किए जा रहे हैं। ताजा मामला खेतों में पौधे लगाने और उन्हें काटने का कानूनी अधिकार देने को लेकर है। सरकार मध्य प्रदेश पौधरोपण प्रोत्साहन विधेयक ला रही है। विधेयक पौधारोपण को फसल (लगाने एवं काटने) जैसे अधिकार देने से संबंधित है। आधा दर्जन राज्यों की योजनाओं का अध्ययन कर इसका खाका तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही प्रारूप को देखकर अंतिम रूप देंगे। वन अधिकारियों का दावा है कि देश में ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य है। इस नए अधिकार से किसानों को आमदनी बढ़ाने का अतिरिक्त माध्यम मिलेगा। किसान अपनी निजी भूमि पर पौधे लगा सकेंगे और जब वे पेड़ बन जाएंगे, तो उन्हें बगैर किसी अनुमति काटकर बेच सकेंगे। वर्तमान में निजी भूमि पर खड़े पेड़ को काटने के लिए अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेना पड़ती है।

सवालों के मिल गए जवाब: विधेयक का मकसद निजी क्षेत्र को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही पेड़ लगाकर अतिरिक्त कमाई का जरिया बनाना भी है। इस कानून के बाद किसान बेझिझक अपने खेत, खलिहान या मकान के आसपास निजी भूमि पर पेड़ लगा सकेंगे और उसे काटकर बेच भी सकेंगे। कानून के प्रारूप में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। शासन स्तर से इसमें कुछ सवाल उठाए गए थे। वन विभाग ने उनका जवाब दे दिया है। अब यह कानून बनने की अंतिम स्थिति में है।

किसान रहेंगे स्वतंत्र: किसान अपने खेत-खलिहान में खड़े पुराने पेड़ों को भी काट सकेंगे। अपने घर से ही लकड़ी बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस, उन्हें इमारती लकड़ी का परिवहन करने के लिए उस सूरत में परिवहन अनुज्ञा पत्र लेना पड़ेगा।

अफसरों का दावा: ओलावृष्टि से नहीं हुआ नुकसान

मुरैना में सरसो 80 और गेहूं की फसल 50 फीसदी चौपट

हकीकत: खड़ी सरसों के दाने तक खेतों में झड़ गए

अवधेश डंडोतिया, मुरैना

जिले में ओलावृष्टि और बारिश ने कई गांवों में फसलों का चौपट कर दिया है। तेज हवा के साथ बरसे ओलों के कारण खेतों में कटने के लिए तैयार खड़ी सरसों की फसल के दाने झड़ गए हैं तो तेज हवा के साथ हुई बारिश ने गेहूं की फसल खेतों में चादर की तरह बिछ गई। मौसम की मार से किसान बेहाल हैं और दफ्तरों में बैठकर अफसर दावा कर रहे हैं कि ओलावृष्टि से नाम मात्र की हुई है। इससे किसानों का कहीं भी नुकसान नहीं हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि प्रकृति की मार से सरसों को 70 से 80 फीसद और गेहूं को 50 फीसद तक नुकसान हुआ है। बारिश के साथ जौरा क्षेत्र के गुर्जा, छिनबरा, डिडोखर, मंजीतपुरा, कलुआपुरा, उत्तमपुरा, सहजपुरा, कोल्हूडाडा, मोहनपुर, खिडोरा, रसोधना, भटियारा, भगोराकलां, बरेंड, सिंगरौली, तिंदोखर, चिन्नौनी से लेकर कैलारस व सबलगढ़ के भी कुछ गांवों में 15 से 20 मिनट तक ओलावृष्टि और फिर झमाझम बारिश हुई है। उधर अंबाह-पोरसा क्षेत्र में भी आंधी व बरसात से गेहूं व सरसों की फसल को नुकसान हुआ है।

खेतों में भरा पानी

गुर्जा, छिनबरा, तिंदोखर, मंजीतपुरा, कलुआपुरा, उत्तमपुरा, सहजपुरा, कोल्हूडाडा, मोहनपुर गांव के खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिन खेतों में सरसों पकी खड़ी थी या कटकर खेत में ही जगह-जगह रखी थी उसके दाने ओलों की आर से खेतों में ही झड़ गए। कई गांवों में इतनी अधिक बारिश व ओलावृष्टि हुई है, वहां खेतों में अभी भी एक फीट से ज्यादा गहरा पानी भर गया। जिसमें गेहूं की फसल डूब गई।

इनका कहना है

हमारी सभी एसएडीओ व अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि गांवों में हल्के-फुल्के ओले गिरे हैं, जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ गांवों में बारिश हुई है पर उससे भी कहीं फसलों में नुकसान की सूचना नहीं आई।

पीसी पटेल, उप संचालक, कृषि

दर्जनों गांवों में ओले से फसल तबाह हो गई। सरसों की फसल में तो 80 फीसद से ज्यादा व गेहूं में 50 फीसद तक नुकसान है। अगर प्रशासन जल्द ही सर्वे कराकर मुआवजे की कार्रवाई नहीं करेगा तो किसानों के साथ हम एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे।

भानू प्रताप सिंह सिकरवार, किसान नेता, जौरा

रतलाम में सरकार के आदेश पर सख्ती खेतों में नरवाई जलाई तो भरोगे जुर्माना

संवाददाता, रतलाम

जिले के खेतों में फसल काटने के बाद नरवाई जलाने पर अब जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के कारण फसल कटाई के बाद बची फसल यानी नरवाई को जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद इसके नरवाई जलाई जाती है तो 15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा। नरवाई जलाने पर अब दो एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान को 2500 रुपए, दो एकड़ से ज्यादा व पांच एकड़ से कम कृषि भूमि वाले को पांच हजार और पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले को पंद्रह हजार तक का जुर्माना लगेगा। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में वसूला जाएगा।

आम समस्या: फसल काटने के बाद बची फसल या नरवाई को जलाना आम समस्या है। अधिकतर जगह किसान श्रम व पैसा बचाने के लिए नरवाई जला देते हैं, लेकिन नरवाई जलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है। साथ ही प्रदूषण भी फैलता है। इस कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है।

नरवाई जलाना खतरनाक: नरवाई जलाना खेती के लिए आत्मघाती है। आग लगाने से भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है। भूमि में उपस्थित सूक्ष्मजीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है। भूमि की ऊपरी परत में ही पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। आग लगाने के कारण पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं।

उर्वरक क्षमता खत्म: नरवाई जलाने से भूमि कठोर हो जाती है। भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। फसलें सूख जाती है। खेत की सीमा पर लगे पेड़-पौधे जल जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता है। धरती गर्म हो जाती है। केंचुए नष्ट हो जाते हैं। इससे भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है।

इनका कहना है

कटाई के बाद बची फसल को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के बाद आदेश जारी किए हैं। सभी कलेक्टर को भी यह आदेश भेजा गया है। इसी महीने से जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

भीका वास्के, साहायक संचालक, कृषि विभाग

923 किसानों को मिला सात करोड़ अनुदान

खेती-बाड़ी को आसान बना रहा मशीनीकरण

जबलपुर। खेती में उन्नत तकनीक अपनाने तथा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने संभाग के किसानों को करीब सात करोड़ रुपए अनुदान जारी किया है। जबलपुर समेत संभाग के सभी जिलों के 923 किसान योजना से लाभांवित होंगे। कृषि अभियांत्रिकी के संभागीय यंत्री एसके चौरसिया ने बताया कि कृषि कार्य में तकनीकी का उपयोग बढ़ा है। मशीनों के उपयोग के चलते फसलों की बोवनी, रोपाई, सिंचाई और कटाई की लागत में कमी आई है। कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती का काम आसान हुआ है। संभाग में बीते एक वर्ष में किसानों को छह करोड़ 87 लाख 16 हजार 701 रुपए अनुदान दिया गया।

कहां के लिए कितना बजट

सिवनी जिले के किसानों को 234 कृषि यंत्रों के लिए एक करोड़ 66 लाख 46 हजार 565 रुपए की अनुदान राशि मुहैया कराई गई है। नरसिंहपुर में 187 कृषि यंत्रों के लिए एक करोड़ 31 लाख 72 हजार 699 रुपए, बालाघाट में 150 कृषि यंत्रों के लिए एक करोड़ 58 लाख 47 हजार 316 रुपए का अनुदान, छिंदवाड़ा में 111 कृषि यंत्रों के लिए 81 लाख 93 हजार 443 रुपए और मंडला में 75 कृषि यंत्रों के लिए 36 लाख 4 हजार 500 रुपए, डिंडोरी में 46 कृषि यंत्रों के लिए 30 लाख 19 हजार 825 रुपए का अनुदान किसानों को प्रदान किया गया। वहीं कटनी जिले में 46 कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 29 लाख 39 हजार 643 रुपए और जबलपुर जिले में 74 कृषि यंत्रों के लिए 52 लाख 92 हजार 710 रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की गई।

इनका कहना है

खेतों की जुताई के लिए पशुओं के बदले ट्रैक्टर का उपयोग दशकों से किया जा रहा है। परंतु अब फसलों की कटाई, बोवनी समेत अन्य कार्य मशीनों के माध्यम से किए जा रहे हैं।

डॉ. रश्मि शुक्ला, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी, जबलपुर

किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी छाई निराशा

उज्जैन में गेहूं का रकबा बढ़ा उत्पादन फिर भी कम

संवाददाता, उज्जैन

क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं का रकबा बढ़ा है। कहा जा रहा था कि इस बार बंपर उत्पादन होगा, लेकिन नहीं हुआ। 12 हजार हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में बोवनी के बाद भी उत्पादन पिछले वर्ष से कम हुआ है। पिछले वर्ष 4 लाख हेक्टेयर में बोवनी की गई थी। उत्पादन 21 लाख मेट्रिक टन हुआ था। इस वर्ष 4 लाख 12 हजार हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। उत्पादन 16 लाख मेट्रिक टन ही रहा। इससे किसानों में निराशा है। जिले में रबी सीजन में बोवनी के कुल रकबे में 75 फीसद क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस बार चार लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोवनी की गई है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12 हजार हेक्टेयर अधिक है। अच्छी बारिश होने से संभावना जताई जा रही थी कि बंपर उत्पादन होगा। फसल अच्छी देख किसान भी खुश थे। फसल पकी तो गेहूं का उत्पादन 15 से 20 फीसद कम पाया गया। सरकार भले ही आंकड़ों में गेहूं का उत्पादन अधिक बताए, हकीकत यह है कि 12 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन होने वाला गेहूं इस बार 8 क्विंटल बीघा पर रह गया है। इससे किसानों को निराशा है।

भाव नहीं मिल रहे

गौरतलब है कि गेहूं की चमक के लिए भी ठंड का गिरना जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वर्तमान में मंडियों में बिकी के लिए आ रहा गेहूं

क्वालिटी में काफी कमजोर है। चमक नहीं होने से तथा गेहूं के दानों में काली टिपकी आ जाने से किसानों को भाव नहीं मिल पा रहा है। कारोबारियों को भी देसावर में व्यापार करने में परेशानी आ रही है।

इनका कहना है

इस बार बंपर उत्पादन की संभावना थी लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। जब गेहूं सवा से डेढ़ माह का था, उस समय ठंडे मौसम की जरूरत थी, लेकिन मौसम ठंडा नहीं हो पाया। जब पकने की तैयारी आई तो फरवरी माह में ठंडा हो गया, नतीजा गेहूं का उत्पादन प्रभावित हो गया।

आरपी शर्मा, कृषि वैज्ञानिक

20 बीघा जमीन में 240 क्विंटल गेहूं पैदावार होने की संभावना थी जो कि घटकर 160 क्विंटल रह गया। इसी तरह कीटिया निवासी गोविंद सिंह के यहां 12 क्विंटल प्रति बीघा की जगह आठ से 9 क्विंटल बीघा उत्पादन हुआ है।

रामसिंह आंजना, किसान, ग्राम चिकली

शिवपुरीः मुफलिसी में जिंदगी काट रहीं ग्राम रन्नौद की पांच साल सरपंच रहीं धनियाबाई का छलका दर्द, बोलीं

रिश्वतखोरी करती तो आलीशान मकान में रहती, गाड़ी में घूमती, लेकिन सीधेपन के कारण कर रही हूं मजदूरी

» 60 साल उम्र होने के बाद भी नहीं मिल रही वृद्धावस्था पेंशन

» जिम्मेदारों की अनदेखी से कुटीर की राशि तक नहीं मिली

खेमराज मौर्य, शिवपुरी

सरपंच शब्द सुनते ही गांव के मुखिया के रूप में किसी दबंग या प्रतिष्ठित चेहरे की छवि उभरकर सामने आती है। सरपंच पांच साल के लिए होता भी गांव का मुखिया है। ग्राम पंचायत के विकास के साथ ग्रामीणों के संबंध में जरूरी फैसले भी लेता है। पांच साल तक रन्नौद की सरपंच रहीं धनियाबाई की कहानी कुछ अलग है। कभी सरपंची के रुतबे के साथ चलती थीं और अधिकारी एक आवाज पर उनका काम भी कर दिया करते थे। अब सरपंची जाने के बाद हालत यह है कि धनियाबाई मुफलिसी में जिंदगी काट रही हैं। मजदूरी कर जंगल से लकड़ियां लाती हैं और उसी से गुजारा करती हैं। इतना ही नहीं, पांच साल सरपंच रहने के बाद भी वे अपने लिए एक पक्का आवास तक नहीं बना पाईं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुटीर के लिए आवेदन किया तो पांच साल में महज दो किश्ते ही आईं। इनमें से दूसरी किश्त तो महज एक हफ्ते पहले ही आई है। इसके चलते वे अभी भी कच्चे मकान में ही रहती हैं। इतना ही नहीं, 60 साल से अधिक उम्र हो जाने के बाद उन्हें वृद्धावस्था पेंशन तक नहीं मिल पा रही है। धनियाबाई कहती हैं कि रिश्वतखोरी करती तो आराम से आलीशान मकान में रहती, चार पहिया गाड़ी में घूमती, लेकिन सीधेपन में ही रह गई। पांच साल से मजदूरी करके और दूसरे के खेतों में बटाई करके पेट पाल रही हूं। हाथ में पैसा नहीं फिर कैसे पार्टी के कार्यक्रमों में जाऊं। किसी बड़े पद पर होती तो मैं भी कुछ करती।

कुछ नहीं मिल रहा

धनियाबाई ने बताया कि सरपंच रहते हुए जिन लोगों पर भरोसा किया और उनके काम करवाए, अब वे भी किनारा कर चुके हैं। स्थिति यह है कि आदिवासी समाज की अन्य महिलाओं के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाना पड़ता है। जब मैं सरपंच थीं तब कुछ नहीं मिला और अब पूर्व सरपंच हूं तो भी कुछ नहीं मिल रहा।

कोई नहीं सुन रहा

पूर्व सरपंच धनियाबाई ने आवास योजना के तहत साल 2016 में आवेदन दिया था। इसके बाद मामला अटका रहा। आठ महीने पहले आवास योजना के तहत पहली किश्त आई थी इसमें 25 हजार रुपए मिले। इससे घर का थोड़ा बहुत काम कराया। अब सात दिन पहले दूसरी किश्त आई है। पहले अधिकारी सब काम कर देते थे, लेकिन अब पद नहीं है और गरीब हूं तो कोई सुनने वाला ही नहीं है।

घर में नौ सदस्य

धनियाबाई के घर में कुल नौ सदस्य हैं। तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। सभी सदस्य कच्चे मकान में ही रहते हैं। पति रामसिंह आदिवासी दूसरे के खेत की रखवाली करने जाते हैं, दसके बदले में 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है।

धार, झाबुआ और अलीराजपुर में टेसू के फूलों को किया जा रहा एकत्रित

होली के लिए हर्बल रंग-गुलाल बनाने में जुटी वन विभाग की टीम

संवाददाता, भोपाल

होली के लिए वन विभाग द्वारा हर्बल रंग-गुलाल बनाने की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। महू, चोरल के साथ-साथ धार, झाबुआ, आलीराजपुर के जंगलों में लघु वनोपज एवं बंधन समितियों के सदस्यों द्वारा पलाश के फूलों को एकत्रित किया जा रहा है। वन विभाग के सीसीएफ हरिशंकर मोहंता ने बताया कि हर्बल रंग-गुलाल त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। झाबुआ व डबलचौकी सहित महू के आशापुरा, बड़गांवदा, बढ़िया और चोरल रेंज के सेंडल, मेंडल तथा रसकुंडिया सहित अन्य जंगलों में बड़ी संख्या में पलाश के पेड़ हैं, जिनके फूल एकत्रित किए जा रहे हैं। धार, झाबुआ, आलीराजपुर के जंगलों में भी बड़ी संख्या में फूल एकत्रित करने में मजदूर पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। लघु वनोपज एवं बंधन समितियों के सहित अन्य मजदूर इस कार्य में लगे हुए हैं।

तैयार होता है रंग-गुलाल

रंग-गुलाल बनाने के लिए पहले 5 दिन तक फूलों को धूप में खूब सुखाया जाता है। उसके बाद मिश्रित कर पानी में डालकर रंग निकाला जाता है। फिर पाउडर मिलाकर उससे रंग व गुलाल तैयार किया जाता है। धार, झाबुआ एवं आलीराजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 200 गांवों में हर्बल रंग-गुलाल के पैकेट तैयार किए जाते हैं। विभाग के मुख्य डिवीजन सहित नौलखा स्थित संजीवनी केंद्र में दुकान लगाई गई थी। दो ही दिन में सारे पैकेट बिक गए। इसी के मद्देनजर इस बार ज्यादा पैकेट तैयार किए जा रहे हैं।

घोषणाः ऋण अदायगी की तारीख अब 30 अप्रैल

शिवराज ने 30 लाख किसानों के खाते में डाली करोड़ों की राहत

संवाददाता, भोपाल

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में भोपाल के मिंटो हाल में आयोजित कार्यक्रम से सिंगल क्लिक पर प्रदेश के लाखों किसानों को राहत राशि की दूसरी किश्त का वितरण किया। सीएम ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के 30 लाख किसानों को राहत राशि की किस्त के 1530 करोड़ और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 17 लाख किसानों के बैंक खातों में 340 करोड़ रुपए अंतरित किए। उन्होंने कहा कि हमने गेहूं की 1.29 करोड़ मीट्रिक टन की रिकार्ड खरीदी की। अपनी सरकार हो और अपना मुख्यमंत्री हो तो किसानों को किस बात का डर। अभी पिछले दिनों हुई बारिश से जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन सभी के खेतों का सर्वे हो रहा है। आंकलन कर मुआवजे की राशि उन्हें दी जाएगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि जनता में बांटने के लिए इतने पैसे कहां से लाते हो। मेरा जवाब होता है कि अगर नियत ठीक हो तो भगवान भी हमारा साथ देता है। गरीबों को लाभान्वित करने का क्रम जारी रहेगा।

सीएम ने कहा कि हमने 44 लाख किसानों को फसल बीमा के 8800 करोड़ का भुगतान किया है। उद्यानिकी फसलों के बीमा का 100 करोड़ रुपया अलग से डाला गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 78 लाख किसानों के बैंक खातों में 5474 करोड़, मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत पहले 1150 करोड़ और 340 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए। पहले फसल नुकसान की राहत की 1550 करोड़ राशि और अब 1530 करोड़ किसानों के खातों में डाले गए हैं। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, सरसों की खरीदी के 36 हजार करोड़ किसानों को भुगतान किया गया। जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्जा दिया गया। इस प्रकार किसानों के खातों में कुल 88 हजार 813 करोड़ रुपया डाला गया। खरीफ फसल की ऋण अदायगी की तारीख भी बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है।

गांवों में अभी से पानी का संकट

» रीवा,सीधी और सतना में हैंडपंप उगलने लगे हवा

» प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में नहीं मिल रहा पानी

» गर्मी की दस्तक, मध्य प्रदेश में छाने लगा जल संकट

» शिवपुरी जिल में निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध

» खंडवा, बड़वानी और खरगोन में भी किल्लत बरकरार

रीवा में क्षेत्रवार हैंडपंप

रीवा	मऊगंज	हनुमना
4690	3771	3405
सिरमौर	**गंगेव**	**जवा**
4046	4650	4748
रायपुर	**त्योंथर**	**नईगढ़ी**
4800	3153	2800

संवाददाता, भोपाल

एक तरफ समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, अथाह जैवविविधता, सोना उगलते खेत और उद्योगों की बड़ी फेहरिस्त से मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की दौड़ में खड़ा नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे ठीक उलट प्रदेश में हर साल गर्मियों की दस्तक के साथ ही लोग बाल्टी-बाल्टी पानी को मोहताज होने लगते हैं। खासकर मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और विंध्य इलाकों में पानी का संकट भयावह होता जा रहा है। मध्यप्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में मार्च के पहले ही सप्ताह में पानी को लेकर कोहराम शुरू हो गया है। कई शहरों में एक से चार दिन छोड़कर जल प्रदाय करना पड़ रहा है। हालांकि सूबे की शिवराज सरकार ने बजट में पीने का पानी के लिए सबसे अधिक फोकस किया है।

प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में भी मार्च महीने में ही पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। इंदौर से ही सटे महू और एशिया के डेट्रायट कहे जाने वाले पीथमपुर में भी पानी के हाल बेहाल हैं। उज्जैन में पानी की त्राहि-त्राहि शुरू हो गई है। जल संकट के लिए बदनाम देवास में इस बार भी गर्मियों की आहट आते ही पानी का संकट खड़ा हो गया है। रतलाम की स्थिति भी ठीक नहीं है। इसी तरह नीमच में भी पानी की किल्लत शुरू हो गई है। उधर, निमाड़ के खंडवा, बड़वानी और खरगोन में भी गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट बढ़ने लगा है। पूर्व मुख्यमत्री कमलनाथ की गृह जिला छिंदवाड़ा में भी पानी की कमी लोगों को खलने लगी है। सागर में जल संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। विंध्य के रीवा-सतना वही शहर हैं, जहां इस साल भारी बारिश हुई थी। लगा था कि इस साल गर्मी में पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन गर्मी की दस्तक के साथ ही यहां के हैंडपंप हवा उगलने लगे हैं।

हैंडपंप सुधार में फर्जीवाड़ा

रीवा जिले में प्रति हैंडपंप सुधार के लिए ठेका कंपनी को 1100 रुपए शासन से भुगतान किया जाता है। सामान्य सुधार कार्य के 535 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन ठेकेदार फर्जी सुधार कार्य का पंचनाम बनाकर लाखों का शासन से भुगतान करा रहे हैं। जब की सच्चाई यह है कि बिगड़े हैंडपंपों पर सुधार कार्य करने वाले कर्मचारी पहुंच ही नहीं पाते हैं। सब ऑफिस में ही बैठकर सुधार कर रहे हैं। जब एक जिले में इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है तो इससे साफ जाहिर है कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ऐसा ही होता होगा। यानि शासन को करोड़ों रुपए की चपट लगाई जा रही है। वहीं जनता पानी के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो रही है।

यहां जल संकट

रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, महू, नीमच, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, खजुराहो में अभी से जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

शिवपुरी जल अकाल घोषित

शिवपुरी जिले में पेयजल संकट को देखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने निजी नलकूपों के खनन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिवपुरी शहर के साथ ही जिले के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में आगामी अन्य आदेश तक जल अकाल जिला घोषित किया गया है।

जबलपुर में जल संकट

जबलपुर में गर्मी का असर धीरे-धीरे अपने पांव पसारने लगा है। राजधानी से लेकर संस्कारधानी तक पानी का संकट लोगों को परेशान कर रहा है। बुंदेलखंड के कुछ जिलों में पानी का संकट इस कदर छा गया है कि पानी जलाशयों की विशेष निगरानी की जा रही है। जबलपुर के शहरी इलाकों में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है।

इनका कहना है

जल जीवन मिशन के लिए 11,128 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से 14 हजार 228 नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 33 लाख ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंचाया जाएगा। बजट में शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 1,364 से बढ़ाकर 5942 करोड़ किया गया है।

तुलसी सिलावट, पीएचई मंत्री

गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जो मौजूदा वित्तीय वर्ष की तुलना में 337 फीसदी ज्यादा है। पहले यह बजट 1364 करोड़ था। जल जीवन मिशन के तहत यह काम पूरा किया जाएगा।

जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री

जल वितरण व्यवस्था एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में निगमायुक्त के साथ बैठक की है। जिसमें रांझी क्षेत्र में जल संकट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। तय हुआ कि जल संकट वाले चिन्हित इलाकों में दो हफ्ते के पहले समस्या का समाधान खोज लिया जाएगा। गर्मी के दिनों में इन इलाकों में भारी जल संकट बन जाता है।

अशोक रोहाणी, विधायक, कैंट, जबलपुर

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)